उसका लगा हुआ पैसा है, उसके मुताबिक, लेकिन माननीय मंत्री जी, यह इतने रेट बढ़ गए हैं 1991 से 1996 तक । .....(व्यवधान).....

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा॰ जगन्नाथ मिश्र): सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य को मालूम है कि खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण करने के लिए जो हमारी मूल्य आयोग गठित है, वह विस्तार से समीक्षा करती है उत्पादन मूल्यों का और उसी हिसाब से सपोर्ट प्राइस की घोषणा सरकार करती है उनकी अनुशंसा पर। आंकड़े बताते हैं कि जो इनपुट्स के मूल्य बढ़े हैं, उस हिसाब से उत्पादन मूल्य भी बढ़े हैं और उसकी सूचना ली है इस आयोग में । वर्ष 1991-1992 में जहां गेंहू का उत्पादन मूल्य 168/- रुपए क्विंटल माना गया था, वहां आज 310/- रुपए प्रति क्विंटल माना गया है इस समय। प्रत्येक साल का अगर देखें तो 1991-92 में 168/- रुपए था, 1992-93 में 250/-, 1993-94 में 281/- 1994-95 में 236/- और 1995-96 में 310/- रुपए । अब यह आयोग तो विचार करती ही है। जो मूल्य बढ़ोतरी है इनपुट्स पर, उस पर विचार करने के उपरांत वह अनुशंसा करती है कि सरकार को सपोर्ट मूल्य क्या करना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य की यह धारणा कि जो यूरिया के या दूसरे पदार्थों के मूल्य बढ़ रहे हैं सरकार उसका ध्यान नहीं रखती, सही नहीं है। सभी बिन्दुओं, पर मूल्य आयोग विचार करते हुए अनुशंसा करती है।

MR. CHAIRMAN: Please put your second supplementary.

श्री इकबाल सिंह: चैयरमेन साहब, सेकेण्ड सप्लीमेंटरी में पूछता हूं, लेकिन यह रेसो के मुताबिक मूल्य नहीं बढ़े हैं, पंजाब के किसान को मूल्य नहीं मिल रहे। मेरी सेकेण्ड सप्लीमेंटरी यह है कि पंजाब राज्य, जो कि बहुत साल टेरारिज्म में फंसा रहा और पंजाब का किसान, जिसकी इन्होंने बहुत अभी प्रशंसा की है, पंजाब के किसान ने बहुत काम किया है एग्रीकल्चर में। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने लाखों टन चावल वहां पड़ा हुआ है और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी 1994 में, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर ने जो उस समय फैसला लिया था कि जो 35 परसेंट बढ़ोतन चावल है उसको यह फाइन और सुपर फाइन आधार देकर के पंजाब से चावल लेंगे, लेकिन आज 96 हो गया, पंजाब का चावल वहीं पड़ा हुआ है। पंजाब का किसान इसके लिए बहुत दुखी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कोई जल्दी से जल्दी ऐसी रिपोर्ट तैयार की है, जिससे किसान को फायदा हो सके और पंजाब का जो चावल गोदामों में पड़ा हुआ है और बाहर पड़ा हुआ है, उसको यह उठा सकें सेंट्रल पूल के लिए?

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: सरकार के ध्यान में सभी राज्यों की समस्याएं आती हैं। यह संभव नहीं हो सकता कि सभी राज्यों की सविस्तार जानकारी सरकार के पास हो। जिन राज्यों की विशेष समस्या हैं, उस पर सरकार ध्यान देती है और किसानों को उत्पादन का मूल्य मिले खुले बाजार में, अगर खुले बाजार में मूल्य नहीं प्राप्त होता है या खाद्यान्न की बिकी नहीं होती है तो सरकार की तरफ से उनके खाद्यान्न खरीदे जाते हैं।

श्री इकबाल सिंह: सर, यह मैंने मूल्य की बात नहीं की, मैंने चावल उठाने की बात की है। सारी इंडस्ट्री फेल हो चुकी है एग्रो इंडस्ट्रीज, राइस शैलर सारे बंद हो चुके हैं।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: अब यह सूचना तो इस समय विस्तार से नहीं है। माननीय सदस्य की जानकारी करा देंगे।

श्री एस. एस. सुरजेवाला: चैयरमेन सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गेंहू की फसल में मंडूसी नाम का एक वीड है, जिसकी शक्ल बिल्कुल गेंहू के साथ मिलती जुलती है और सच तो यह है कि मंडूसी वीड जो है, उसने पूरे गेंहू का जो प्रोडक्शन है, पैदावार है उसको 25 से लेकर 50 प्रतिशत कम कर दिया है, तो आपके मंत्रालय ने इस बारे में क्या उपाय किए हैं ताकि किसान की रक्षा की जा सके और यह मंडूसी जो वीड है वह नष्ट हो सके? क्योंकि कितने ही स्प्रे करवाएं, सारे स्प्रे के बावजूद भी मंडूसी जो है वह गेंहू के ऊपर से जाती नहीं है। दूसरा, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा ....(व्यवधान)....

श्री सतीश अग्रवाल: एक का जवाब तो आने दें।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: जो हमारे अनुसंधान केन्द्र भिन्न-भिन्न राज्यों में, उन अनुसंधान केन्द्रों में जो जानकारी प्राप्त होती है, उस हिसाब से हम किसानों को हिदायत जारी करते है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, अनुसंधान के मामले में इसे प्रस्तुत कर देंगे।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट

*122. श्री सुन्दर सिंह भंडारी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने बड़े पैमाने पर उपयोग में आने वाली दवाइयों की उत्पादन लागत एवं कीमतों का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उस में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं, और

(ख) क्या ब्यूरो को नए सिरे से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) सरकार का एक निशेषज्ञ निकाय-औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी आई सी पी) समय-समय पर लागत और-तकनीकी अध्ययन करता है तथा डी पी सी ओ की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध प्रपुंज औषधों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(ख) रिपोर्ट की मूल्य निर्धारण अवधि समाप्त होने पर बी आई सी पी चालू आंकड़े/लागत के आधार पर नई रिपोर्ट तैयार करता है।

Pre-examination coaching centres for the weaker sections

*126. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of Pre-examination coaching centres in the country for the weaker sections of the society;

(b) the number out of the above which were established between 1991 and 1996;

(c) the number of persons given coaching in these centres during the last three years and the number of persons (service-wise) who have been appointed to various services; and

(d) the steps being taken by Government to widen the scope of these centres?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Under the scheme of pre-examination coaching for weaker sections operated by the Ministry of Welfare and Human Resource Development 360 institutions are provided grant-in-aid for implementing the scheme by Govt., Deptt. NGOs. Universities and Colleges.

(b) 140 number of coaching centres have been provided grant-in-aid during 1991 and 1996 out of 360 number montion at (a).

(c) The details of the number of candidates coached and results reported till the end of February, 1996 year-wise as follows:

Year	No. of candidates coached	No. of successful candidates	(%)
1992-93	7193	209	2.9
1993-94	5802	358	6.1
1994-95	7844	349	4.4.

(d) The following steps will be taken to widen the scope of the coaching centres.

(i) Publicise the coaching scheme through mass-media.

(ii) Identification and selection of reputed organisations.

(iii) Emphasis will be on setting up of coaching centres as for as possible in areas where target group candidates reside in sufficient numbers so that the coaching facilities are made available to them in their proximity.

(iv) Steps will be taken to cover as many new courses as possible for providing training under the scheme taking into account the emerging sunrise areas of employment, namely computer field, hotal management etc.

Increase the Quota of IPCL products for Kerala

*127. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to increase the quota of products of IPCL Baroda for the State of Kerala;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the State-wise allotment of various products of IPCL?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): *(a)* to *(c)* In pursuance to the liberalised economic regime, the Government has no policy of price and distribution controls over all petrochemical products. Accordingly, the Indian Petrochemicals Corporation Limited has no system of State-wise quota for marketing